

[2023] 2 एस. सी. आर 793

क.

प्रमोद सिंगला बनाम.

भारत संघ व अन्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 1051) अप्रैल 10, 2023

[कृष्ण मुरारी और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974-निवारक निरोध-केंद्र सरकार, निरोध प्राधिकरण और सलाहकार बोर्ड को हिरासत में लेकर प्रतिनिधित्व-केंद्र सरकार यदि प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने से पहले सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य है-क्या पंकज कुमार मामले और अब्दुल्ला कुन्ही मामले के बीच कोई विसंगति मौजूद है-आयोजित:नहीं-चूंकि ये दोनों निर्णय सहजीवी रूप से मौजूद हैं और कोफेपोसा अधिनियम के भीतर दो अलग-अलग प्राधिकरणों पर लागू होते हैं, इसलिए निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है-पंकज कुमार निर्णय के अनुसार सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करने का जनादेश केंद्र सरकार पर लागू होगा. हालाँकि, हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण, सरकार से स्वतंत्र होने के नाते, सलाहकार बोर्ड के निर्णय के बिना अपना निर्णय पारित कर सकता है-वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-बंदी ने विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी और सरकार दोनों को एक अभ्यावेदन भेजा है।-हिरासत में रखने वाले प्राधिकरण ने सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्रता से प्रतिनिधित्व पर निर्णय लिया, और इसलिए, पंकज कुमार निर्णय का उल्लंघन नहीं किया-सरकार ने पंकज कुमार निर्णय की प्रतीक्षा की।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

793

794 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

- हालाँकि, अपीलार्थी को हिरासत की अवधि समाप्त होने के आधार पर पहले ही रिहा कर दिया गया था-भारत का संविधान-कला।21, 22(5) - निवारक निरोध अधिनियम, 1950 -एस. 3.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 21,22 (5)-आयोजित:जिन मामलों में अवैध दस्तावेजों की आपूर्ति की गई है, वहां संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजने के अपने अधिकार का लाभ उठाने में उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है-इस प्रकार, अनुच्छेद 22 (5) के तहत राहत और अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देने वाले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान दूषित हो जाते हैं-निवारक निरोध के मामलों में, अनुच्छेद 21 और 22 (5) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक प्रक्रियात्मक अनियमितता, निरोध के पक्ष में उपार्जित की जानी चाहिए।

आपराधिक कानून-निवारक निरोध कानून-दुर्व्यवहार/दुरुपयोग-आयोजित:इस तरह के कानूनों की बहुत गंभीर जांच की जानी चाहिए और इसका उपयोग केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

डी.

पकड़ना:**1.** भारत में निवारक निरोध कानून एक औपनिवेशिक विरासत है, और इसका दुरुपयोग और दुरुपयोग होने की बहुत संभावना है। जिन कानूनों में राज्य को मनमानी शक्तियां प्रदान करने की क्षमता है, उनकी सभी परिस्थितियों में बहुत गंभीर जांच की जानी चाहिए और उनका उपयोग केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए। निवारक निरोध के मामलों में, जहां बंदी को गिरफ्तारी में रखा जाता है, न कि उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए, बल्कि एक संभावित अपराध के लिए जो वह कर सकता है, अदालतों को हमेशा बंदी के पक्ष में संदेह का हर लाभ देना चाहिए, और यहां तक कि प्रक्रियात्मक अनुपालन में थोड़ी सी भी त्रुटियों का परिणाम बंदी के पक्ष में होना चाहिए। बंदी को, कोफेपोसा अधिनियम के तहत निवारक निरोध के मामलों में, निरोध प्राधिकरण, सरकार और सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद **22 (5)** के अनुसार इन अभ्यावेदनों पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि प्रतिनिधित्व या तो सरकार या निरोध अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है, हालांकि, यदि प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया जाता है, तो निरोध अवधि जारी रहती है। [पैरा **21,22**] **[802-ई-जी; 803-ए-बी]**

ई.

च

जी.

2. क्या पंकज कुमार मामले और अब्दुल्ला कुन्ही मामले के बीच कोई विसंगति है और यदि ऐसा टकराव मौजूद है तो क्या कानून के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए?

एच.

795

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ।

क.

पंकज कुमार मामले का फैसला निवारक निरोध अधिनियम, **1960** के संदर्भ में पारित किया गया था और अब्दुल्ला कुन्ही मामले को कोफेपोसा अधिनियम के संदर्भ में पारित किया गया था। दोनों अधिनियमों की धारा **3** निवारक निरोध का प्रावधान करती है। दोनों कानूनों के तहत निरोध आदेश या तो सरकार द्वारा या विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता है। हालांकि, निवारक निरोध अधिनियम की धारा **3** के तहत, विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को, निरोध के **12** दिनों के भीतर, निरंतर निरोध के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है, और केवल तभी जब सरकार इसे मंजूरी देती है तो निरोध जारी रखा जा सकता है। सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी से सरकार को सत्ता का हस्तांतरण है, जिससे सरकार **12** दिनों के प्रारंभिक अंतराल के बाद हिरासत में लेने वाली प्राधिकरण बन जाती है। हालांकि, कोफेपोसा अधिनियम में, सरकार से इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण और सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र दो अलग-अलग निकाय बने हुए हैं। कोफेपोसा अधिनियम और अन्य निवारक निरोध कानूनों के बीच इस अंतर को इस अदालत ने कमलेश कुमार के मामले में बरकरार रखा है।

ग

डी.

ईश्वरदास पटेल बनाम भारत संघ और अन्य। अगर पंकज कुमार

निर्णय को कोफेपोसा अधिनियम में विशेष रूप से सशक्त अधिकारी और सरकार के बीच इस अंतर के आलोक में पढ़ा जाता है, यह पाया जाता है कि पंकज कुमार निर्णय और अब्दुल्ला कुन्ही निर्णय के बीच कोई टकराव नहीं है, क्योंकि पंकज कुमार निर्णय, केंद्र सरकार को सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करने के लिए अनिवार्य करते हुए, केवल इसलिए करता है क्योंकि केंद्र सरकार निवारक निरोध अधिनियम में निरोध अधिकारी है। सरल शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा न करने का जनादेश प्रभावी रूप से केंद्र सरकार के लिए नहीं है, बल्कि केवल हिरासत में लिए गए अधिकारी के लिए है। कोफेपोसा अधिनियम में, चूंकि हिरासत में लेने का अधिकार सरकार से अलग है, इसलिए पंकज कुमार निर्णय और अब्दुल्ला कुन्ही निर्णय दोनों लागू होंगे, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में। पंकज कुमार का निर्णय, चूंकि यह सरकार के निरोध प्राधिकारी होने के संदर्भ में दिया गया था, केवल कोफेपोसा अधिनियम के तहत निरोध प्राधिकारी/विशेष रूप से सशक्त अधिकारी पर लागू होगा। हालांकि अब्दुल्ला कुन्ही निर्णय, चूंकि इसे कोफेपोसा अधिनियम के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसके तहत जनादेश होगा

ई.

च

जी.

एच.

796 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

क.

स्पष्ट रूप से केवल सरकार पर लागू होता है, न कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर। सरल शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि सलाहकार बोर्ड की प्रतीक्षा न करने का आदेश केवल हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर लागू होगा। हालांकि, अब्दुल्ला कुन्ही मामले के अनुसार, सरकार को सलाहकार मंडल के फैसले का इंतजार करना चाहिए। चूंकि ये दोनों निर्णय सहजीवी रूप से मौजूद हैं और कोफेपोसा अधिनियम के भीतर दो अलग-अलग प्राधिकरणों पर लागू होते हैं, इसलिए निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है, और इसलिए कानून के इस बिंदु को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही तय हो चुका है। जैसा कि अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है, कोई भी स्पष्ट संघर्ष हल हो जाता है, और निर्णयों के दोनों सेट उक्त अधिनियम के भीतर सहजीवी और सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करते हैं, उनके बीच कोई तनाव मौजूद नहीं है। पंकज कुमार निर्णय के अनुसार सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करने का आदेश केंद्र सरकार पर लागू होगा, हालांकि, हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण, सरकार से स्वतंत्र होने के कारण, सलाहकार बोर्ड के निर्णय के बिना अपना निर्णय पारित कर सकता है। चूंकि कोई संघर्ष मौजूद नहीं है, इसलिए कानून के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। [अनुच्छेद 31, 33-35] [811-G-H; 813-F-G; 814-A-D; 815-B-D]

ग

डी.

पंकज कुमार चक्रवर्ती और ओ. आर. एस. वी. पश्चिमी राज्य

बंगाल (1969) 3 एससीसी 400: [1970] 1 एससीआर 543; के. एम.

ई.

अब्दुल्ला कुन्ही और बी. एल. अब्दुल खादर बनाम भारत संघ

& ओ. आर. एस. (1991) 1 एससीसी 476: [1991] 1 एससीआर 102-चर्चा की गई।

3. यदि इस न्यायालय के दो संवैधानिक निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है, तो क्या अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में 60 दिनों की देरी के आधार पर विवादित निरोध आदेश को रद्द किया जा सकता है?

च

वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-बंदी ने अपने अधिकारों का लाभ उठाते हुए, विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी और सरकार दोनों को एक अभ्यावेदन भेजा। वर्तमान मामले में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने सलाहकार मंडल के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्रता से प्रतिनिधित्व पर निर्णय लिया, और इसलिए, पंकज कुमार निर्णय का उल्लंघन नहीं किया। वर्तमान मामले में सरकार ने सलाहकार मंडल के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया। यह भी अब्दुल्ला कुन्ही मामले के निर्णय के अनुसार किया गया था, क्योंकि सरकार ए

जी.

एच.

797

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ।

एक अलग प्राधिकरण, सलाहकार मंडल के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य है। निरोध प्राधिकारी और सरकार दोनों ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के भीतर सटीक रूप से काम किया है, और इसलिए विवादित निरोध आदेश इस आधार पर निरस्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। [पारस 36-38] [815-D-H]

4. क्या यहाँ अपीलार्थी को प्रस्तुत किए गए चीनी भाषा में लिखे गए अवैध दस्तावेज विवादित निरोध आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार हैं?

जिन मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अवैध दस्तावेजों की आपूर्ति की गई है, वहां संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजने के अपने अधिकार का लाभ उठाने में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए एक गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है, क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करते समय उसकी नजरबंदी के आधार पर स्पष्टता नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत राहत और प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति देने वाले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को दूषित कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अज्ञात खतरे से अपना बचाव नहीं कर सकता है। निवारक निरोध के मामलों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 (5) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक प्रक्रियात्मक अनियमितता, निरोध के पक्ष में उपाजित की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को विदेशी भाषा में अवैध दस्तावेज प्रदान किए गए हैं। ये वही दस्तावेज हैं जिन पर अधिकारियों ने अपीलार्थी को हिरासत में लेने के लिए भरोसा किया है। इसके अलावा, इस मामले में समानता का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि समान परिस्थितियों वाले एक अन्य सह-बंदी को पहले ही उसके खिलाफ निरोध आदेश को रद्द करने की राहत दी जा चुकी है। जबकि अपीलार्थी को पहले ही निरोध अवधि की समाप्ति के आधार पर रिहा कर दिया गया है, कानून के मुद्दे पर स्पष्टता के लिए, यह माना जाता है कि विवादित निरोध आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। [पारस 39, 42, 43 और 45] [816-बी-सी; 817-ए-सी; 818-ए]

ग

डी.

ई.

च

जी.

कमलेश कुमार ईश्वरदास पटेल बनाम भारत संघ

ओआरएस। (1995) 4 एससीसी 51; [1995] 3 एस. सी. आर. 279; हरिकिसन

v. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (1962) सप. 2 एससीआर 918; ज्ञान चंद बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. (सीआरएल।)

39 2011-पर भरोसा किया।

एच.

798 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

क.

हरधन साहा बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य **[1975] 1 एस. सी. आर. 778;** अंकित अशोक जालान बनाम भारत संघ और अन्य। **(2020) 16**

एससीसी 127:[2020] 2 एस. सी. आर. 1047; जयनारायण सुकुल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1970) 1 एस. सी. सी. 219:[1970] 3 एससीआर

225; फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम डब्ल्यू. सी. खम्ब्रा और अन्य।

(1980) 2 एससीसी 275:[1980] 2 एस. सी. आर. 1095-संदर्भित। निर्णीत विधि संदर्भ

1975] 1 एससीआर 778

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

[1991] 1 एससीआर 102

चर्चा की।

पैरा **18 (iii)**

[2020] 2 एससीआर 1047

संदर्भित किया गया है

पैरा **18 (iii)**

ग

[1970] 1 एससीआर 543

चर्चा की।

पैरा **18 (iii)**

[1970] 3 एससीआर 225

संदर्भित किया गया है

पैरा **18 (iii)**

[1980] 2 एससीआर 1095

संदर्भित किया गया है

पैरा **28**

[1995] 3 एससीआर 279

पर भरोसा किया

पैरा **32**

डी.

[1962] सप.2 एस. सी. आर. **918** पैरा **40** पर निर्भर था।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 1051।

2022 के डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. संख्या 1205 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.11.2022 के निर्णय और आदेश से।

ई.

विक्रम चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, निखिल जैन, ऋषि सहगल, केशवम चौधरी, सुश्री हरगुन संधू, सुश्री अरवीन सेखों, सुश्री प्रभनीर स्वानी, सुश्री दिव्या जैन, सागर जुनेजा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव, अक्षित प्रधान, सुश्री आकंशा कौल, नकुल चेंगप्पा के. के., शरत नांबियार, अनुज श्रीनिवास उदुपा, चित्रांशु शर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

च

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, न्या.

जी.

छुट्टी मंजूर की गई।

2. वर्तमान अपील नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) लिखित याचिका (सी. आर. एल.) में पारित किए गए विवादित फैसले और अंतिम आदेश दिनांक 03.11.2022 के खिलाफ निर्देशित है। 2022 का सं. 1205 जिसके तहत अपीलार्थी की ए को रद्द करने की याचिका

एच.

799

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने में देरी के आधार पर उनके खिलाफ निरोध आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था।

तथ्य

3. संक्षेप में, वर्तमान अपील से संबंधित तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ चीनी, ताइवानी और दक्षिण कोरियाई नागरिकों का एक सिंडिकेट कुछ भारतीय नागरिकों के साथ मिलकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग/रीवर्किंग मशीनों आदि के ट्रांसफॉर्मर में सोना छिपाकर एयर कार्गो के माध्यम से भारत में सोने की तस्करी करने की प्रथा में था।

4. ऐसा ही एक कार्गो मेसर्स हेल्दी फ्यूचर लीडर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भारत में आयात किया जा रहा था और इसके नई दिल्ली हवाई अड्डे पर दिल्ली कार्गो कॉम्प्लेक्स में पहुंचने की संभावना थी।

ग

5. 18.11.2021 और 19.11.2021 पर, उक्त खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 के अधिकारियों द्वारा कथित खेप की जांच की गई और 80.126 किलोग्राम 24 कैरेट विदेशी मूल का सोना उक्त खेप से 'E' और 'I' आकार की प्लेटों के रूप में बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य Rs.39,31,38,219-था।

डी.

6. अपीलार्थी एक संदिग्ध होने के कारण, उसकी दुकान की डी. आर. आई. अधिकारियों द्वारा जाँच की गई और उसके परिसर से 7 सोने के टुकड़े बरामद किए गए, जिनका बाजार मूल्य ₹2,680/- था।

ई.

7. प्रत्यर्थी प्राधिकरण ने उपर्युक्त सिंडिकेट के चार अलग-अलग स्थानों पर तलाशी भी ली और उनके खिलाफ आपत्तिजनक सबूत मिलने के आधार पर 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। 8. 20.11.2021 पर, अपीलार्थी को सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के साथ प्रतिवादी नं.4 प्राधिकरण, जिसके बाद उन्हें एल. डी. के समक्ष पेश किया गया। सीएमएम, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 9. अपीलार्थी ने तब विद्वान सी. एम. एम. के समक्ष जमानत मांगी, और 13.12.2021 के आदेश के अनुसार उसे जमानत दे दी गई।

च

10. आई. डी. 1 दिनांकित चार अलग-अलग आदेशों के माध्यम से, उक्त अपराध में आरोपी सभी चार विदेशी नागरिकों को एल. डी. द्वारा जमानत भी दी गई थी। सीएमएम, और आगे, दिनांकित 21.12.2021 के आदेश के माध्यम से, सीएमएम ने भारतीय मूल के सह-आरोपी नीरज वाष्णेय को भी जमानत दे दी।

जी.

11. जमानत पर अपीलार्थी की रिहाई के बाद, डी. आर. आई. ने उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त शर्त को शामिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

एच.

800

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

जमानत आदेश अपीलार्थी को हर सोमवार को 11 बजे डी. आर. आई. के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश देता है: 00 हूँ, और वही दिया गया था।

12. 19.01.2022 पर, डी. आर. आई. ने प्रतिवादी संख्या 2 को अपीलार्थी के खिलाफ कोफेपोसा अधिनियम के तहत निरोध का आदेश जारी करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, और बाद में प्रतिवादी संख्या 2 निरोध प्राधिकरण ने 01.02.2022 पर अपीलार्थी के खिलाफ विवादित निरोध आदेश पारित किया। अपीलार्थी को डी. आर. आई. द्वारा 04.02.2022 पर गिरफ्तार किया गया था।

13. 24.02.2022 पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, दिल्ली उच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया था, और बाद में, अपीलार्थी द्वारा 02.03.2022 पर प्रतिवादी संख्या 2 निरोध प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन भेजा गया था जिसे 15.03.2022 पर खारिज कर दिया गया था।

ग

14. इस बीच, 10.03.2022 पर, अपीलार्थी ने केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन पत्र भेजा, और बाद में 04.04.2022 पर, उन्होंने सलाहकार बोर्ड को एक और अभ्यावेदन दिया। 15. सलाहकार बोर्ड के समक्ष सुनवाई 18.04.2022 पर समाप्त हुई,

और 09.05.2022 पर, केंद्र सरकार ने 60 दिनों की देरी के बाद सलाहकार बोर्ड की सलाह पर प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया। 16. अपीलार्थी ने तब उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की जिसमें उसके खिलाफ निरोध आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसे दिनांक 03.11.2022 के विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

डी.

ई.

17. इस न्यायालय ने बाद में, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी को उसके पिता की मृत्यु के कारण अंतरिम राहत के रूप में हिरासत से रिहा कर दिया, और बाद में, अपीलार्थी के खिलाफ विवादित निरोध आदेश की समाप्ति के कारण, उसे हिरासत से रिहा कर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा किए गए तर्क

च

18. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि: I. भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के अनुसार, निवारक निरोध के मामलों में बंदी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए, और अभ्यावेदन पर विचार करने में अत्यधिक देरी निरोध आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार है।

जी.

II. इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार सलाहकार बोर्ड की सिफारिश की प्रतीक्षा करने के लिए किसी भी मजबूरी में नहीं है और उसे हिरासत में लिए गए लोगों के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने में स्वतंत्र रूप से और बिना किसी देरी के कार्य करना चाहिए।

एच.

801

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

क.

III. इसके अलावा, एल. डी. अपीलार्थी के वकील का तर्क है कि के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही के मामले में इस न्यायालय के निर्णय & बी. एल. अब्दुल खादर बनाम भारत संघ और अन्य। 1 और अंकित अशोक जालान बनाम भारत संघ और अन्य। 2 निर्णय, ये दोनों संविधान पीठ के फैसले हैं, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को सलाहकार बोर्ड के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जो पंकज मामले में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसलों का सीधा उल्लंघन है

कुमार चक्रवर्ती और ओआरएस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 3 और जयनारायण सुकुल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 4, और स्पष्ट संघर्ष के कारण, इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है।

ग

IV. यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को उसके निवारक निरोध के आधार के रूप में प्रदान किए गए दस्तावेज अवैध और चीनी भाषा में थे, और इसलिए इस आधार पर भी अपीलार्थी के खिलाफ विवादित निरोध आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

डी.

जवाबदेहों द्वारा किए गए तर्क

19. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री के. एम. नटराज का तर्क है कि:

I. पंकज मामले में कोई विसंगति नहीं है।

ई.

(ऊपर) और अशोक जालान मामला (ऊपर) जैसा कि तर्क दिया गया है

अपीलार्थी द्वारा। अपीलार्थी द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे निवारक निरोध अधिनियम के संदर्भ में हैं, जबकि,

अशोक जालान मामला (ऊपर) और अदुल्ला कुनी मामला

(ऊपर दिए गए) कोफेपोसा अधिनियम के संदर्भ में हैं, और यदि पंकज मामले (ऊपर दिए गए) कोफेपोसा अधिनियम के संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि वे कोफेपोसा अधिनियम में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी और केंद्र सरकार के बीच अंतर हैं, तो दोनों संवैधानिक पीठ के फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं है।

च

जी.

II. अशोक जालान मामले (उपरोक्त) के अनुसार, नजरबंदी के कारण

प्राधिकरण और केंद्र सरकार स्वतंत्र होने के कारण

1 (1991) 1 एससीसी 476 2 (2020) 16 एससीसी 127 3 (1969) 3 एससीसी 400 4 (1970) 1 एससीसी 219

एच.

802

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. अधिनियम के तहत, सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करने का आदेश केंद्र सरकार पर मौजूद है, और इसलिए 60 दिनों की देरी निरोध आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

मुद्दे

20. पक्षों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए उपर्युक्त तर्कों के आलोक में, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित तीन मुद्दे उत्पन्न होते हैं। II. क्या पंकज के बीच कोई विसंगति है।

कुमार मामला (ऊपर) और अब्दुल्ला कुन्ही मामला

(ऊपर), और यदि ऐसा टकराव मौजूद है तो क्या कानून के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए?

ग

II. यदि इस न्यायालय के दो संवैधानिक निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है, तो क्या अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में 60 दिनों की देरी के आधार पर विवादित निरोध आदेश को रद्द किया जा सकता है?

डी.

III. क्या यहाँ अपीलार्थी को प्रस्तुत किए गए चीनी भाषा में लिखे गए अवैध दस्तावेज विवादित निरोध आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार हैं?

21. तैयार किए गए मुद्दों से निपटने से पहले, हमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण लगता है कि भारत में निवारक निरोध कानून एक औपनिवेशिक विरासत है, और इसका दुरुपयोग और दुरुपयोग होने की बहुत संभावना है। जिन कानूनों में राज्य को मनमानी शक्तियां प्रदान करने की क्षमता है, उनकी सभी परिस्थितियों में बहुत गंभीर जांच की जानी चाहिए और उनका उपयोग केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए। निवारक निरोध के मामलों में, जहां बंदी को गिरफ्तारी में रखा जाता है, न कि उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए, बल्कि एक संभावित अपराध के लिए जो वह कर सकता है, अदालतों को हमेशा बंदी के पक्ष में संदेह का हर लाभ देना चाहिए, और यहां तक कि प्रक्रियात्मक अनुपालन में थोड़ी सी भी त्रुटियों का परिणाम बंदी के पक्ष में होना चाहिए।

ई.

च

प्रश्न 1-क्या पंकज कुमार मामले और अब्दुल्ला कुन्ही मामले के बीच कोई विसंगति है और यदि ऐसा टकराव मौजूद है तो क्या कानून के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए?

जी.

22. इस प्रश्न को तय करने के उद्देश्य से, हमें पहले अपने निवारक ए के खिलाफ एक बंदी को प्राप्त अधिकारों के बारे में विस्तार से बताना चाहिए।

एच.

803

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

उनके प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निरोध। बंदी को, कोफेपोसा अधिनियम के तहत निवारक निरोध के मामलों में, निरोध प्राधिकरण, सरकार और सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के अनुसार इन अभ्यावेदनों पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि प्रतिनिधित्व या तो सरकार या निरोध अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है, हालांकि, यदि प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया जाता है, तो निरोध अवधि जारी रहती है।

23. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी, जो निवारक निरोध में है, ने केंद्र सरकार, निरोध प्राधिकरण और सलाहकार बोर्ड को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। यह अपीलार्थी का मामला है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपीलार्थी प्राधिकारी के प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से विचार किया, लेकिन सरकार ने इस पर विचार करने के लिए 60 दिन का समय लिया। अपीलार्थी के अनुसार 60 दिनों की यह देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है और विवादित निरोध आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार है।

ग

डी.

24. हालांकि, सरकार का दावा है कि 60 दिनों की देरी पूरी तरह से उचित है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पहले सलाहकार बोर्ड की सलाह का इंतजार कर रही थी। इस संघर्ष के आलोक में, जिस व्यापक मुद्दे का जवाब देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या केंद्र सरकार अपने निर्णय पर आने से पहले सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य है या नहीं। इसका उत्तर देने के लिए, हमें प्रासंगिक मामले कानूनों को देखना चाहिए जो सरकार के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी और ऐसी परिस्थिति में हिरासत में लिए गए व्यक्ति।

ई.

25. पंकज कुमार मामले (सुप्रा) में याचिकाकर्ता

निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के तहत उनके खिलाफ पारित निरोध आदेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई, इस आधार पर कि सरकार उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में विफल रही और इसे केवल सलाहकार बोर्ड को पारित कर दिया। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि सरकार को सलाहकार बोर्ड से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, और सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए सरकार पर कोई अधिदेश नहीं है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ यहाँ निकाले जा रहे हैं:

च

जी.

“यह सच है कि खंड (5) सकारात्मक भाषा में यह प्रावधान नहीं करता है कि प्रतिनिधित्व किसे किया जाना है और जब किया जाता है, तो किसके द्वारा इस पर विचार किया जाना है। लेकिन अभिव्यक्तियाँ “के रूप में

एच.

804 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

उस खंड में जल्द से जल्द “और” जल्द से जल्द अवसर “स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आधारों को लागू किया जाना है और एक अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है ताकि बंदी को यह दिखाने में सक्षम बनाया जा सके कि उसकी नजरबंदी अनुचित है और चूंकि कोई अन्य प्राधिकरण जिसे इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है, यह केवल हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण हो सकता है जिसे यह किया जाना है जिसे इस पर विचार करना होगा। यद्यपि खंड (5) स्पष्ट शब्दों में नहीं कहता है, इसलिए यह अपने प्रावधानों से इस प्रकार कहता है कि यह निरोध प्राधिकारी है जिसे निरोध को अभ्यावेदन देने और इस प्रकार किए जाने पर इस पर विचार करने का जल्द से जल्द अवसर देना होता है कि क्या इसका आदेश गलत है या उस कानून के विपरीत है जो उसे निरोध करने में सक्षम बनाता है। अब्दुल करीम मामले में दिए गए दृष्टांत [अब्दुल करीम बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, (1969) 1 एस. सी. सी. 433] से पता चलता है कि अनुच्छेद 22 के खंड (5) में न केवल आधार प्रस्तुत करने और प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर देने के लिए उपयुक्त सरकार का दायित्व शामिल है, बल्कि आवश्यक निहितार्थ से उस प्रतिनिधित्व पर विचार करने का दायित्व भी है। ऐसा दायित्व स्पष्ट रूप से बंदी को दिखाने का अवसर देने के लिए और उपयुक्त सरकार को आदेश के खिलाफ किसी भी आपत्ति पर विचार करने का अवसर देने के लिए प्रदान किया गया है, जिसे बंदी उठा सकता है ताकि किसी भी व्यक्ति को गलती से या अन्यथा, गलत तरीके से गिरफ्तार और हिरासत में न लिया जाए। यदि यह इरादा था कि ऐसे प्रतिनिधित्व पर सरकार द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जहां एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है और ऐसे मामलों में प्रतिनिधित्व पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है, न कि उपयुक्त सरकार द्वारा, खंड (5) ने निरोध करने वाले प्राधिकरण को निर्देश नहीं दिया होगा कि वह निरोध को जल्द से जल्द अवसर प्रदान करे। उस मामले में शब्द अधिक उचित रूप से होते कि प्राधिकरण को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने और बोर्ड को सूचित करने का अवसर देने के बाद बोर्ड की राय प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन उन मामलों में क्या होगा जहां हिरासत 3 महीने से कम समय के लिए है और बोर्ड की राय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है? यदि वकील का तर्क सही होना है तो ऐसे मामलों में प्रतिनिधित्व पर उपयुक्त सरकार या बोर्ड और प्रतिनिधित्व के अधिकार और संबंधित दायित्व द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

805

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

इस तरह का प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर देने के लिए उपयुक्त सरकार को निरर्थक माना जाएगा। प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के दायित्व को लागू करने में, खंड (5) केवल 3 महीने या उससे कम समय के लिए निरोध के आदेशों और लंबी अवधि के लिए निरोध के आदेशों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। दायित्व दोनों प्रकार के आदेशों पर लागू होता है। खंड में यह नहीं कहा गया है कि प्रतिनिधित्व पर पूर्व श्रेणी के मामलों में उपयुक्त सरकार द्वारा और बाद के वर्ग के मामलों में बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है। हमारे विचार में अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (5) से यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सरकार पर दोहरा दायित्व है और बंदी के पक्ष में दोहरा अधिकार है, अर्थात्, (1) उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किए गए निरोध की अवधि के बावजूद उसका प्रतिनिधित्व प्राप्त करना और (2) बोर्ड द्वारा अपनी राय देने से पहले मामले की परिस्थितियों के आलोक में एक बार फिर वह प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। यदि उस अभ्यावेदन के आलोक में बोर्ड को लगता है कि हिरासत के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो सरकार को हिरासत के आदेश को रद्द करना होगा और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त करना होगा। इस प्रकार, जबकि सरकार यह पता लगाने के लिए अभ्यावेदन पर विचार करती है कि क्या आदेश प्रासंगिक कानून के तहत अपनी शक्ति के अनुरूप है, बोर्ड इस तरह के अभ्यावेदन पर अपनी राय पर पहुंचने के दृष्टिकोण से विचार करता है कि क्या निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। उपयुक्त सरकार का दायित्व है कि वह बंदी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करे और उस प्रतिनिधित्व पर विचार करे, जो बोर्ड का गठन करने और अन्य सामग्रियों के साथ प्रतिनिधित्व को बोर्ड को सूचित करने के सरकार के दायित्व से अलग है ताकि वह अपनी राय बना सके और ऐसी राय प्राप्त कर सके।

ग

डी.

ई.

च

इस निष्कर्ष को अधिनियम के अन्य प्रावधानों से मजबूती मिलती है। अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (5) के अनुरूप, अधिनियम की धारा 7 निरोध करने वाले प्राधिकारी को अपनी निरोध की तारीख से पांच दिनों के भीतर निरोध के आधार प्रस्तुत करने और निरोध को उपयुक्त सरकार के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करने का आदेश देती है। धारा 8 और 9 उपयुक्त सरकार को एक सलाहकार बोर्ड का गठन करने और उसे स्थापित करने का आदेश देती है।

जी.

एच.

806 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

निरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर निरोध के लिए आधार, निरोध का प्रतिनिधित्व और उस अधिकारी की रिपोर्ट भी जहां निरोध का आदेश एक अधिकारी द्वारा दिया जाता है न कि सरकार द्वारा। धारा 7 के तहत दायित्व धारा 8 और 9 के तहत दायित्व से काफी अलग है। यदि प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा नहीं बल्कि केवल बोर्ड द्वारा विचार के लिए था जैसा कि तर्क दिया गया था, तो यह प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि इसे सरकार को संबोधित किया जाना चाहिए न कि सीधे बोर्ड को। सरकार का उद्देश्य केवल एक संचारक प्राधिकरण बनना नहीं हो सकता था और न ही इस पर विचार किया जा सकता था कि उसे उस प्रतिनिधित्व पर सख्ती से बैठना चाहिए और इसके गठन के बाद इसे बोर्ड को भेजना चाहिए। अनुच्छेद 22 के खंड (5) और अधिनियम की धारा 7 में आकस्मिक भाषा की आवश्यकता नहीं होती यदि प्रतिनिधित्व पर सरकार को नहीं बल्कि बोर्ड को विचार करना पड़ता। धारा 13 राज्य के वकील के तर्क का जवाब भी देती है। उस धारा के तहत राज्य सरकार और केंद्र

सरकार को निरोध के आदेश को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार है। यह शक्ति स्पष्ट रूप से सरकार को उचित कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की गई है, जहां उसे किए गए अभ्यावेदन पर, यह पाया जाता है कि विचाराधीन आदेश को संशोधित किया जाना चाहिए या यहां तक कि रद्द भी किया जाना चाहिए। जाहिर है, संसद का इरादा यह नहीं हो सकता था कि उपयुक्त सरकार को उस अभ्यावेदन पर विचार किए बिना धारा 13 के तहत एक आदेश पारित करना चाहिए जिसे धारा 7 के तहत संबोधित किया गया है।

ग

डी.

ई.

उपरोक्त कारणों से हम अब्दुल करीम मामले में निर्णय से सहमत हैं [अब्दुल करीम बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, (1969) 1 एस. सी. सी. 433]। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को एक संवैधानिक अधिकार था और राज्य सरकार पर उनके अभ्यावेदन पर विचार करने का एक संबंधित संवैधानिक दायित्व था, भले ही वे उनके मामलों को सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से पहले या बाद में किए गए थे और ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ निरोध के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से हमारे लिए इन आदेशों के खिलाफ उठाई गई अन्य आपत्तियों की जांच करना आवश्यक नहीं है। इसलिए याचिका की अनुमति दी जाती है, याचिकाकर्ता 15 और 36 के खिलाफ हिरासत के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और हम निर्देश देते हैं कि उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए।"

च

जी.

एच.

807

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

क.

26. इसके अलावा, जयनारायण सुकुल मामले (सुप्रा) में, वही

इस मुद्दे पर इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया था, जिसमें उसने पंकज कुमार मामले (सुप्रा) में सिद्धांतों को दोहराया और कहा कि केंद्र सरकार को सलाहकार बोर्ड से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, और सलाहकार बोर्ड से सुने बिना बंदी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय ले सकती है। सुविधा के उद्देश्य से, उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“वर्तमान मामले में, पश्चिम बंगाल राज्य न केवल अभ्यावेदन पर विचार करने में अत्यधिक देरी करके बल्कि सलाहकार मंडल की राय प्राप्त होने तक विचार करने के लिए भी संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इस अत्यधिक देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जाँच करने वाले अधीक्षक ने हलफनामे की पुष्टि नहीं की। राज्य ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि यह लंबी देरी क्यों हुई। वर्तमान मामले में अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उपयुक्त प्राधिकारी निष्क्रियता और स्वतंत्र निर्णय की कमी के कारण अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा।”

ग

डी.

27. हरधन साहा मामले (सुप्रा) में, एक और

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निवारक निरोध के मामलों में बंदी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बीच के अंतर पर विचार किया, और यह कहा गया कि यदि मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से पहले अभ्यावेदन किया गया था, तो निरोध प्राधिकारी को ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए, लेकिन यदि मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद अभ्यावेदन किया जाता है, तो निरोध प्राधिकारी पहले इस पर विचार करेगा और फिर इसे सलाहकार बोर्ड को भेजेगा। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

ई.

च

“बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व पर विचार करना राज्य का दायित्व है। सलाहकार बोर्ड के पास पूरी सामग्री की जांच करने की पर्याप्त शक्ति है। बोर्ड अधिक सामग्री के लिए भी कॉल कर सकता है। बोर्ड बंदी को उसके अनुरोध पर बुला सकता है। बोर्ड के संविधान से पता चलता है कि इसमें न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति शामिल होते हैं। बोर्ड का संविधान निष्पक्ष खेल और सिद्धांतों के मूल सिद्धांतों का पालन करता है।

जी.

एच.

808 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

प्राकृतिक न्याय। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है कि मौखिक सुनवाई होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 8, जो राज्य पर प्रतिनिधित्व पर विचार करने का दायित्व डालती है, बंदी को वे सभी अधिकार प्रदान करती है जिनकी अनुच्छेद 22 (5) द्वारा गारंटी दी गई है। सरकार अनिवार्य रूप से यह पता लगाने के लिए अभ्यावेदन पर विचार करती है कि क्या आदेश कानून के तहत शक्ति के अनुरूप है। दूसरी ओर, बोर्ड इस बात पर विचार करता है कि क्या प्रतिनिधित्व के आलोक में हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक प्रतिबंध की तर्कसंगतता पर विचार करने में एक तत्व हैं जहां अनुच्छेद 19 लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करने के चरण में, राज्य सरकार का दायित्व वैसा ही है जैसा अनुच्छेद 22 (5) में निहित है। अधिनियम की धारा 8 पूरी तरह से अनुच्छेद 22 (5) के अनुरूप है क्योंकि यह धारा संविधान के प्रावधानों का पालन करती है। यदि मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से पहले बंदी का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण प्रतिनिधित्व पर विचार करता है। यदि मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद कोई प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व भेजने से पहले इस पर विचार करेगा।”

ग

डी.

ई.

28. इसके बाद, फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम डब्ल्यू. सी. खम्ब्रा और अन्य के मामले में। 5, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने जयनारायण सुकुल (सुप्रा) के निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों पर विचार किया, और हालांकि यह उपरोक्त मामले के सिद्धांतों से सहमत था, लेकिन यह कहते हुए एक टिप्पणी की कि जब यह कहा गया था कि सरकार को प्रतिनिधि मंडल को भेजने से पहले प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेना चाहिए, तो जोर समय पर नहीं था, बल्कि प्रतिनिधित्व पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जिम्मेदारी सरकार पर थी। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ था कि सरकार को सलाहकार बोर्ड से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां निकाले जा रहे हैं:

च

जी.

“निवारक निरोध के मामलों में न्यायालय की भूमिका के बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है: यह शाश्वत सतर्कता का होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं है और इसे अक्षुण्ण रखने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। अदालत का

5 (1980) 2 एससीसी 275 ए

एच.

809

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

रिट अवैध हिरासत के खिलाफ अंतिम बीमा है। संविधान अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुरूप होने का आदेश देता है और न्यायालय इसका सटीक अनुपालन करता है। अनुच्छेद 22 (5) बंदी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने का अधिकार देता है। यहाँ लॉ रिपोर्ट्स एक कहानी बताती है और एक सबक सिखाती है। यह है कि बंदी का प्रमुख दुश्मन और प्रतिनिधित्व करने का उसका अधिकार न तो उच्च-हाथ है और न ही मतलबी है, बल्कि अनौपचारिक उदासीनता, मूर्खतापूर्ण असंवेदनशीलता, नौकरशाही मशीन की दिनचर्या और लालफीताशाही है। जयनारायण सुकुल बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य में न्यायालय द्वारा प्रतिपादित चार सिद्धांत। [जयनारायण सुकुल बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, (1970) 1 एस. सी. सी. 219:1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 92] के साथ-साथ अन्य मामलों में प्रतिपादित अन्य सिद्धांतों का उद्देश्य उदासीनता, असंवेदनशीलता, दिनचर्या और लालफीताशाही से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाना है और इस प्रकार बंदी को एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार सुनिश्चित करना है। हम सहमत हैं: (1) निरोधक प्राधिकारी को निरोधक को अभ्यावेदन देने का बहुत जल्दी अवसर प्रदान करना चाहिए, (2) निरोधक प्राधिकारी को जितनी जल्दी हो सके अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए, और यह, अधिमानतः, प्रतिनिधित्व को सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से पहले होना चाहिए, (3) प्रतिनिधित्व को बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए, और (4) प्रतिनिधित्व के निरोधक प्राधिकारी द्वारा विचार बोर्ड द्वारा सुनवाई या उसकी रिपोर्ट से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चरण में अभियान आवश्यक है। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि समय-अनिवार्यता कभी भी निरपेक्ष या जुनूनी नहीं हो सकती है। न्यायालय की टिप्पणियों को इतना नहीं समझा जाना चाहिए। मामले की आवश्यकताओं (हम "परिस्थितियों" शब्द का उपयोग करने से बचते हैं) के आधार पर छूट होनी चाहिए। एक ऐसे मामले की अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है जिसमें एक बंदी बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट देने से पहले एक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिससे हिरासत में लिए गए प्राधिकारी के लिए इस पर विचार करना या समय पर बोर्ड को भेजना असंभव हो जाता है या एक ऐसा मामला जहाँ एक बंदी सलाहकार बोर्ड द्वारा इस संदर्भ को लेने से कुछ समय पहले हिरासत में लिए गए प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करता है कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी उससे पहले प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं कर सकता है, लेकिन उसे स्वयं विचार किए बिना केवल बोर्ड को भेज सकता है। इस तरह के कई

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

810 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

परिस्थितिसभ अनिवार्य समयसँ बाध्यकारी विचलन उत्पन्न कऽ सकैत अछि। लेकिन सुस्त उदासीनता के लिए कोई छूट नहीं दी जा सकती है। अनावश्यक विलंब के लिए कोई छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन, जहाँ कानूनी पेचीदगियाँ और तथ्यात्मक प्रभाव

शामिल हैं, वहां आवश्यक परामर्श के लिए निश्चित रूप से छूट दी जानी चाहिए। समय-अनिवार्यता से थोड़े से प्रस्थान की आवश्यकता को समझाने का बोझ हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर है।

हम पहले ही जयनारायण सुकुल बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य में प्रतिपादित चार सिद्धांतों के साथ अपनी सहमति व्यक्त कर चुके हैं। [जयनारायण सुकुल बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, (1970) 1 एस. सी. सी. 219:1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 92] हम एक अवलोकन करेंगे। जब वहां यह कहा गया कि सरकार को सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व भेजने से पहले प्रतिनिधित्व पर अपने निर्णय पर आना चाहिए, तो जोर समय के बिंदु पर नहीं था, बल्कि इस आवश्यकता पर था कि सरकार को बोर्ड से स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व पर विचार करना चाहिए।"

ग

डी.

29. तथापि, अब्दुल्ला कुन्ही (सुप्रा) के मामले में, जहां कोफेपोसा अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता की निवारक निरोध को उसी विवादित आधार पर चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने दोनों मुद्दों पर विचार करते हुए कहा था कि मामले के समक्ष प्रतिनिधित्व कब प्रस्तुत किया जाता है और मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद, दोनों परिस्थितियों के लिए, यह अभिनिर्धारित किया था कि सरकार को प्रतिनिधित्व पर अपना निर्णय लेने से पहले सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उपर्युक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को नीचे निकाला जा रहा है:

ई.

च

"हम फ्रांसेस कोरली मुलिन मामले [(1980) 2 एस. सी. सी. 275 में टिप्पणियों से सहमत हैं: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 419] प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए अनिवार्य समय कभी भी पूर्ण या जुनूनी नहीं हो सकता है। यह आवश्यकताओं और प्रतिनिधित्व किए जाने के समय पर निर्भर करता है। मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से पहले अभ्यावेदन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजने से पहले अभ्यावेदन को निपटाने का समय नहीं हो सकता है। उस स्थिति में प्रतिनिधित्व को ए को भी भेजा जाना चाहिए।

जी.

एच.

811

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

बंदी के मामले के साथ सलाहकार मंडल। बंदी का मामला बोर्ड को भेजे जाने के बाद अभ्यावेदन प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में भी प्रतिनिधित्व को सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए बशर्ते बोर्ड ने कार्यवाही समाप्त नहीं की हो। दोनों स्थितियों में सलाहकार मंडल की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले अभ्यावेदन पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। न ही यह कहा जा सकता है कि सरकार ने बोर्ड की रिपोर्ट का अनावश्यक रूप से इंतजार करते हुए अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी की है। ऐसी स्थितियों में सरकार के लिए बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार करना उचित है। यदि बोर्ड गुण-दोष के आधार पर निरोध के लिए कोई सामग्री नहीं पाता है और तदनुसार रिपोर्ट करता है, तो सरकार निरोध के आदेश को रद्द करने के लिए बाध्य है। दूसरा, भले ही बोर्ड यह विचार व्यक्त करता है कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है, सरकार प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद हिरासत को रद्द कर सकती है। बोर्ड को नजरबंदी की तारीख से ग्यारह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। सलाहकार मंडल बंदी को उसके अनुरोध पर सुन सकता है। बोर्ड के संविधान से पता चलता है कि इसमें ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं जो न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति होते हैं। इसलिए यह उचित है कि सरकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उपरोक्त दो स्थितियों में प्रतिनिधित्व पर विचार करे। यदि सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के बाद सरकार को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व भेजने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। सरकार को इससे जल्द से जल्द निपटना होगा और इसका निपटारा करना होगा।"

ग

डी.

ई.

च

30. जबकि पहली नज़र में, ऐसा लग सकता है कि निर्णयों के दो सेटों के बीच घर्षण है, हालाँकि, एक गहरा निरीक्षण अन्यथा साबित होगा। निर्णयों के दो समूहों को समझने के लिए, हमें पहले उन प्रासंगिक प्रावधानों को देखना चाहिए जिनके तहत ये निर्णय पारित किए गए थे।

जी.

31. पंकज कुमार केस (सुप्रा) का फैसला पारित किया गया था

निवारक निरोध अधिनियम, **1960** और अब्दुल्ला कुन्ही मामले (सुप्रा) के संदर्भ को कोफेपोसा अधिनियम के संदर्भ में पारित किया गया था। निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले दो अधिनियमों की धारा **3**, एक तैयार संदर्भ के लिए, एक तालिका चार्ट में यहाँ पुनः प्रस्तुत की जा रही है:

एच.

812 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

813

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

क.

32. जैसा कि उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों से देखा जा सकता है, दोनों कानूनों के तहत निरोध आदेश या तो सरकार द्वारा या विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता है। हालाँकि, निवारक निरोध अधिनियम की धारा 3 के तहत, विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को, निरोध के **12** दिनों के भीतर, निरंतर निरोध के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है, और केवल तभी जब सरकार इसे मंजूरी देती है तो निरोध जारी रखा जा सकता है। सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया

अनिवार्य रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी से सरकार को सत्ता का हस्तांतरण है, जिससे सरकार 12 दिनों के प्रारंभिक अंतराल के बाद हिरासत में लेने वाली प्राधिकरण बन जाती है। हालाँकि, कोफेपोसा अधिनियम में, सरकार से इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण और सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र दो अलग-अलग निकाय बने हुए हैं। कोफेपोसा अधिनियम और अन्य निवारक निरोध कानूनों के बीच इस अंतर को इस अदालत ने कमलेश के मामले में बरकरार रखा है।

ग

कुमार ईश्वरदास पटेल बनाम भारत संघ और अन्य। **6**, प्रासंगिक

उपरोक्त निर्णय के उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

डी.

“दूसरा आधार यह है कि केंद्र सरकार हिरासत में लेने वाली प्राधिकरण बन जाती है क्योंकि इसके जारी होने के समय से ही इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है, जो कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना के विपरीत है जो अन्य निवारक निरोध कानूनों, अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971 और निवारक निरोध अधिनियम, 1950 से अलग है।”

ई.

33. अगर हम पंकज कुमार के फैसले (सुप्रा) को पढ़ें

च

कोफेपोसा अधिनियम में विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी और सरकार के बीच यह अंतर, हम पाते हैं कि कोई टकराव मौजूद नहीं है

पंकज कुमार जजमेंट (सुप्रा) और अब्दुल्ला के बीच

कुन्ही निर्णय (सुप्रा), पंकज कुमार निर्णय के बाद से, केंद्र सरकार को सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करने के लिए अनिवार्य करते हुए, केवल इसलिए करता है क्योंकि केंद्र सरकार निवारक निरोध अधिनियम में निरोध अधिकारी है। सरल शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा न करने का जनादेश प्रभावी रूप से केंद्र सरकार के लिए नहीं है, बल्कि केवल हिरासत में लिए गए अधिकारी के लिए है।

जी.

एच.

6 (1995) 4 एस. सी. सी 51

814

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

34. सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. अधिनियम में, चूंकि हिरासत में लेने का अधिकार सरकार से अलग है, दोनों, पंकज कुमार निर्णय

(ऊपर) और अब्दुल्ला कुन्ही निर्णय (ऊपर) लागू होगा, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में। पंकज कुमार निर्णय (ऊपर), क्योंकि यह

सरकार के निरोध प्राधिकरण होने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, जो केवल कोफेपोसा अधिनियम के तहत निरोध प्राधिकारी/विशेष रूप से सशक्त अधिकारी पर लागू होगा। हालाँकि, अब्दुल्ला कुन्ही निर्णय (ऊपर दिया गया), चूंकि इसे कोफेपोसा अधिनियम के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसके तहत अधिदेश पूरी तरह से केवल सरकार पर लागू होगा, न कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर। सरल शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि सलाहकार बोर्ड की प्रतीक्षा न करने का आदेश केवल हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर लागू होगा। लेकिन सरकार ने,

ग

अब्दुल्ला कुन्ही मामले (ऊपर) के अनुसार, के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए

सलाहकार बोर्ड। चूंकि ये दोनों निर्णय सहजीवी रूप से मौजूद हैं और कोफेपोसा अधिनियम के भीतर दो अलग-अलग प्राधिकरणों पर लागू होते हैं, इसलिए निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है, और इसलिए कानून के इस बिंदु को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही तय हो चुका है। एक ही अधिनियम के भीतर दो अलग-अलग क्षेत्रों में दोनों निर्णयों के इस अनुप्रयोग को अशोक जालान निर्णय (उपरोक्त) में स्पष्ट किया गया है, उक्त निर्णय से प्रासंगिक उद्धरण यहां निकाला जा रहा है:

डी.

“हम इस बात से अवगत हैं कि हम जो दृष्टिकोण ले रहे हैं, वह कुछ विसंगति का कारण बन सकता है और जब ऐसे विशेष रूप से सशक्त अधिकारी, जिन्होंने निरोध का आदेश पारित किया था, और उपयुक्त सरकार के समक्ष एक साथ अभ्यावेदन किए जाते हैं, तो स्पष्ट द्वंद्व हो सकता है। यदि हम के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही [के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही बनाम भारत संघ, (1991) 1 एस. सी. सी. 476 में पैरा 16 के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं: 1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 613] उपयुक्त सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह सलाहकार बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करे, जबकि साथ ही विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी जिसने हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के रूप में काम किया था, वह पूर्ण अभियान के साथ प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए बाध्य होगा। कभी-कभी हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी, विशेष रूप से सशक्त अधिकारी और उपयुक्त सरकार के साथ-साथ सलाहकार बोर्ड को प्रतियों के साथ एक एकल प्रतिनिधित्व तैयार किया जाता है। ऐसी स्थितियों में असंगति होगी जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिसे किसी स्तर पर ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, ऐसी कठिनाई या असंगति ए को धारण करने का आधार नहीं हो सकती है।

ई.

च

जी.

एच.

815

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

कि एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए भी उन्हीं सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाएगा जो के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही [के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही बनाम भारत संघ, (1991) 1 एस. सी. सी. 476 के पैरा 16 में निर्धारित किए गए हैं: 1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 613]"

35. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कोई भी स्पष्ट संघर्ष, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है, हल हो गया है, और निर्णयों के दोनों सेट उक्त अधिनियम के भीतर सहजीवी और सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करते हैं, उनके बीच कोई तनाव मौजूद नहीं है। सलाहकार के निर्णय की प्रतीक्षा करने का जनादेश

बोर्ड, पंकज कुमार निर्णय (सुप्रा) के अनुसार, लागू होगा

ग

केंद्र सरकार, हालांकि, हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण, सरकार से स्वतंत्र होने के कारण, सलाहकार बोर्ड के निर्णय के बिना अपना निर्णय पारित कर सकती है। चूंकि कोई संघर्ष मौजूद नहीं है, इसलिए कानून के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, और इसलिए हम उत्तरदाताओं के पक्ष में मुद्दा संख्या 1 रखते हैं।

डी.

आई. एस. यू. ई. II-यदि इस न्यायालय के दो संवैधानिक निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है, तो क्या अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में **60** दिनों की देरी के आधार पर विवादित निरोध आदेश को रद्द किया जा सकता है?

36. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-बंदी ने अपने अधिकारों का लाभ उठाते हुए, विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी और सरकार दोनों को एक अभ्यावेदन भेजा। वर्तमान मामले में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने सलाहकार बोर्ड के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्रता से प्रतिनिधित्व पर निर्णय लिया और इसलिए, पंकज कुमार का उल्लंघन नहीं किया।

ई.

निर्णय (ऊपर)।

च

37. वर्तमान मामले में सरकार ने सलाहकार मंडल के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया। यह अब्दुल्ला कुन्ही मामले (उपरोक्त) के निर्णय के अनुसार भी किया गया था, क्योंकि सरकार, एक अलग प्राधिकरण होने के नाते, सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य है।

जी.

38. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, यह देखा जा सकता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी और सरकार दोनों ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के भीतर सटीक रूप से काम किया है, और इसलिए विवादित हिरासत आदेश इस आधार पर निरस्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए हम दूसरा मुद्दा प्रत्यर्थी के पक्ष में रखते हैं।

एच.

816 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

आई. एस. एस. यू. ई. III-क्या यहाँ अपीलार्थी को प्रस्तुत किए गए चीनी में लिखे गए अवैध दस्तावेज विवादित निरोध आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार हैं?

39. जिन मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अवैध दस्तावेजों की आपूर्ति की गई है, वहां संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजने के अपने अधिकार का लाभ उठाने में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है, क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करते समय उसकी नजरबंदी के आधार पर स्पष्टता नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत राहत और प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति देने वाले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को दूषित कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अज्ञात खतरे से अपना बचाव नहीं कर सकता है।

ग

40. हरिकिसन बनाम महाराष्ट्र राज्य और

ओआरएस। 7, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निवारक निरोध के मामलों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत निहित सिद्धांतों के अनुसार, निरोध करने वाले प्राधिकारी को निरोध के आधारों की व्याख्या करनी चाहिए, और उसी के समर्थन में और निरोध द्वारा समझी गई भाषा में सामग्री प्रदान करनी चाहिए। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

डी.

“...अपीलार्थी पर दिए गए आदेश के समर्थन में आधार चौदह टाइप किए गए पृष्ठों में थे और तेरह वर्षों की अवधि में उनकी गतिविधियों का उल्लेख किया गया था, इसके अलावा उनके और अन्य व्यक्तियों से संबंधित बड़ी संख्या में अदालती कार्यवाही का उल्लेख किया गया था, जिन पर उनके सहयोगी होने का आरोप था। अपीलार्थी को स्क्रिप्ट और भाषा में अनुवाद प्रदान किए बिना प्रकृति के एक जटिल आदेश का केवल मौखिक स्पष्टीकरण, जिसे वह समझता था, हमारे निर्णय में, आधारों को संप्रेषित करने और आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिए जाने के अधिकार से इनकार करने के बराबर होगा।

ई.

च

41. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि एक सह-बंदी, श्री नीरज वाष्ण्य को पहले ही राहत दी जा चुकी है, और उनकी नजरबंदी के आधार के रूप में उन्हें प्रदान किए गए अवैध चीनी दस्तावेजों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा उनके नजरबंदी आदेश को रद्द कर दिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक वर्तमान निरोध का संबंध है, अपीलार्थी की परिस्थितियाँ सह-बंदी के मामले के समान हैं, जिसके निरोध आदेश को रद्द कर दिया गया था।

जी.

7 (1962) सप.2 एससीआर 918 ए

एच.

817

प्रमोद सिंगला बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

42. पुनरावृत्ति के लिए, हम यह कहना महत्वपूर्ण पाते हैं कि निवारक निरोध के मामलों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 (5) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हर प्रक्रियात्मक अनियमितता को निरोध के पक्ष में अर्जित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को विदेशी भाषा में अवैध दस्तावेज प्रदान किए गए हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये वही दस्तावेज हैं जिन पर अधिकारियों ने अपीलार्थी को हिरासत में लेने के लिए भरोसा किया है।

43. इसके अलावा, इस मामले में समानता का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि समान परिस्थितियों वाले एक अन्य सह-बंदी को पहले ही उसके खिलाफ निरोध आदेश को रद्द करने की राहत दी जा चुकी है। मैं

ग

ज्ञान चंद बनाम भारत संघ और अन्न का मामला। 8, यह न्यायालय जबकि

निरोध आदेश को रद्द करने का निर्णय लेते हुए, स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में जहां समान रूप से रखे गए सह-बंदी को पहले ही निरोध आदेश को रद्द करने की राहत दी जा चुकी है, समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए, और समान राहत अन्य समान रूप से रखे गए बंदियों को भी दी जानी चाहिए। उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हम अपीलार्थी के पक्ष में मुद्दा III रखते हैं।

डी.

निष्कर्ष

44. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत में निवारक निरोध कानून एक औपनिवेशिक विरासत हैं, और इस तरह, बेहद शक्तिशाली कानून हैं जो राज्य को मनमाने ढंग से शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में, जहां सरकार द्वारा शक्ति के निर्बाध विवेकाधिकार की संभावना है, इस न्यायालय को ऐसे कानूनों से उत्पन्न मामलों का अत्यधिक सावधानी और कष्टप्रद विवरण के साथ विश्लेषण करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन है। निवारक निरोध के मामलों में सरकार द्वारा प्रत्येक प्रक्रियात्मक कठोरता का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, और प्रक्रिया में प्रत्येक चूक से निरोध के मामले में लाभ होना चाहिए। निवारक निरोध की परिस्थितियों में न्यायालयों को वह कर्तव्य प्रदान किया जाता है जिसे संविधान द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया है, जो व्यक्तिगत और नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण है। नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का यह कार्य, न केवल व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों की रक्षा करना है, बल्कि हमारे संवैधानिक लोकाचार को संरक्षित करने का भी कार्य है, जो ब्रिटिश राज्य की मनमानी शक्ति के खिलाफ संघर्षों की एक श्रृंखला का एक उत्पाद है।

ई.

च

जी.

8 () 2011 का 39

एच.

818

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

45. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, जबकि अपीलार्थी को पहले ही निरोध अवधि की समाप्ति के आधार पर रिहा कर दिया गया है, कानून के मुद्दे पर स्पष्टता के लिए, हम मानते हैं कि विवादित निरोध आदेश को दरकिनार किया जा सकता है, और वर्तमान अपील तदनुसार अनुमत है।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.